

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 758]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 29, 2016/चैत्र 9, 1938

No. 758]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 29, 2016/CHAITRA 9, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

**का.आ. 1229 (अ).**—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 3442(अ) में अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट, पुणे के संबंध में अधिसूचना की तारीख को “दिनांक 17 मार्च, 2013”, के स्थान पर “7 दिसंबर, 2015” पढ़ा जाए।

[सं. 1/2016/फा०सं.27015/4/2015-एसओ (नैट.कॉम)]

मक्खन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th March, 2016

**S.O. 1229(E).**—In the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 3442(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), in respect of Ayodhya Charitable Trust, Pune, the date of Notification i.e. “17<sup>th</sup> March 2013”, may be read as “7<sup>th</sup> December, 2015”.

[No. 1/2016/F.No.27015/4/2015-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

**शुद्धिपत्र**

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

**का.आ. 1230(अ).**—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 3455(अ), दिनांक 17 दिसंबर, 2015 में 'ब्लाइंड परसन्स' एसोसिएशन ट्रस्ट के पते में "10/2, शम्सुल हुडा रोड, कोलकाता," के स्थान पर "6वीं पंचाननतला रोड, दूसरा तल, कोलकाता-700029" पढ़ा जाए।

[सं. 2/2016/फा० सं.27015/4/2015-एसओ (रा.स.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 29th March, 2016

**S.O. 1230(E).**—In the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 3455(E) dated 17<sup>th</sup> December, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), relating to the address of the Trust 'Blind Persons' Association,' "10/2, Shamsul Huda Road, Kolkata", may be read as "6B Panchanantala Road, 2<sup>nd</sup> Floor, Kolkata - 700029".

[No. 2/2016/F.No.27015/4/2015-SO(NAT.COM)]

MAKKHANLAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

**का.आ. 1231(अ).**—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 07.05. 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1030(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "प्रभाकर पाटिल एजुकेशन सोसायटी, एटी एवं पोस्ट-वेश्वी, तालुका-अलीबाग, जिला रायगट-228627 महाराष्ट्र" द्वारा "प्रभाकर पाटिल एजुकेशन सोसायटी की शिक्षा विकास परियोजना" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 9.75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 16 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत को 9.75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 14.89 करोड़ रुपये तक बढ़ाए जाने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत को 9.75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 14.89 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की सिफारिश की है ; तथापि, कंपनी अधिनियम और कंपनियों (सीएसआर) नियम, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर धारा 35 क ग के तहत कोई छूट लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "प्रभाकर पाटिल एजुकेशन सोसायटी, एटी एवं पोस्ट-वेश्वी, तालुका-अलीबाग, जिला रायगट-228627 महाराष्ट्र" द्वारा चलाई जा रही "प्रभाकर पाटिल एजुकेशन सोसायटी की शिक्षा विकास परियोजना" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और;

(ख) दिनांक 07.5.2012 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 1030(अ) को निम्नलिखित आशय के लिए और आगे संशोधित करती है नामतः-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 16 के सामने तालिका में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में “9.75 करोड़ रुपये” अक्षरों, अंकों और शब्दों को “14.89 करोड़ रुपये” अक्षरों, अंकों और शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर धारा 35 कग के तहत कोई छूट लागू नहीं होगी;

[सं. 4/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016-एस ओ ( एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2016

**S.O. 1231(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1030(E) dated 7.5.2012 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 16, “Prabhakar Patil Education Society’s Education Development Project” by “Prabhakar Patil Education Society, At & Post-Veshvi, Taluka-Alibag, District Raigat-228627, Maharashtra”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 9.75 crore for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs. 9.75 crore to Rs. 14.89 crore;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and enhancing the project cost from Rs. 9.75 crore to Rs. 14.89 crore. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Prabhakar Patil Education Society’s Education Development Project”, which is being carried out by “Prabhakar Patil Education Society, At & Post-Veshvi, Taluka-Alibag, District Raigat-228627, Maharashtra”, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18;

(b) further amends the said notification number S.O. 1030(E) dated 7.5.2012, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 16, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under Section of 35AC of Income Tax Act, 1961 for the letters, figures and word “Rs. 9.75 crore” the letters, figures and word “Rs. 14.89 crore” shall be substituted.

(c). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 4/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

**का.आ. 1232 (अ).**— जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 18 अक्टूबर, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 1045 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “अरावली विकास मंडल, 302, मैत्री कॉओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, गोलांगी मिल रोड, पारेल, मुंबई-400012” द्वारा “जिला सिंधीदुर्ग महाराष्ट्र में भवन निर्माण, स्टाफ के लिए आवासीय क्वार्टर, मशीनों/उपकरणों की खरीद, अरावली मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर तैयार करना” की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2002-03 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 1 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 3 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 144(अ) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2005-06 को प्रारंभ होने वाले

एक वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 15.02.2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 238(अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 17 मई, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 1132(अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 14.05.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1069(अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तेरह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ; तथापि, कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियम, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर धारा 35 कग के तहत कोई छूट लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “अरावली विकास मंडल, 302, मैत्री कॉओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, गोलांगी मिल रोड, पारेल, मुंबई-400012” द्वारा चलाई जा रही “जिला सिंधीदुर्ग महाराष्ट्र में भवन निर्माण, स्टाफ के लिए आवासीय क्वार्टर, मशीनों/उपकरणों की खरीद, अरावली मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर तैयार करना” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए 548.90 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर धारा 35 कग के तहत कोई छूट लागू नहीं होगी।

[सं. 5/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016-एस ओ ( एन. सी)]

मन्मथ लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2016

**S.O. 1232(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.1045(E) dated the 18<sup>th</sup> October, 2001, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 1, for “Construction of building, residential quarters for staff, purchase of equipments/machines, furnishing of Aravali Medical and Research Centre at Aravali, District Sindhidurg, Maharashtra” by Aravali Vikas Mandal, 302, Maitri Cooperative Housing Society, Golangi Mill Road, Parel, Mumbai-400012 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003; which was extended further vide notification number S.O.144(E) dated the 3<sup>rd</sup> February, 2006 for a period of one year beginning with assessment year 2005-2006 and which was further extended vide notification number S.O.238(E) dated 15.02.2007 for a period of three years commencing with financial year 2006-07 and which was extended further vide notification S.O.No.1132 (E) dated 17<sup>th</sup> May, 2010 for a period of three years beginning with the financial year 2009-10 and which was further extended vide S.O. No. 1069(E) dated 14.05.2012 for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond thirteen years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s

35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- Section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project for "Construction of building, residential quarters for staff, purchase of equipments/machines, furnishing of Aravali Medical and Research Centre at Aravali, District Sindhidurg, Maharashtra" which is being carried out by Aravali Vikas Mandal, 302, Maitri Cooperative Housing Society, Golangi Mill Road, Parel, Mumbai-400012, without any change in the approved cost of Rs. 548.90 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial years 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 5/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

**का.आ. 1233 (अ).-** जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 627 (अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "स्वयंकृशि, 17, श्री मलानी हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी, इंडियन एयर लाइन कॉलोनी, त्रिनुलघेरी, सिकंदराबाद-500015" द्वारा "दिमागी रूप से कमजोर, सेरेब्रल पल्सी, ओटिज्म और बहु-विकलांगता वाले लोगों के लिए प्रशिक्षण और आवासीय सुविधाएं" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 6.22 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 19 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ; तथापि, कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियम, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर धारा 35 क ग के तहत कोई छूट लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "स्वयंकृशि, 17, श्री मलानी हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी, इंडियन एयर लाइन कॉलोनी, त्रिनुलघेरी, सिकंदराबाद-500015" द्वारा चलाई जा रही "दिमागी रूप से कमजोर, सेरेब्रल पल्सी, ओटिज्म और बहु-विकलांगता वाले लोगों के लिए प्रशिक्षण और आवासीय सुविधाएं" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए 6.22 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर धारा 35 क ग के तहत कोई छूट लागू नहीं होगी।

[सं. 6/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016-एस ओ( एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th March, 2016

**S.O. 1233(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 627(E) dated 12.03.2013 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 19, "Training Centre and Housing Facilities for persons with mental challenges, cerebral palsy, autism and multiple disabilities" by "Swayamkrushi, 17, Sri Malani Housing Co-operative Society, Indian Air Line Colony, Trinulgherry, Secunderabad – 500 015", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 6.22 crore for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Training Centre and Housing Facilities for persons with mental challenges, cerebral palsy, autism and multiple disabilities.", which is being carried out by "Swayamkrushi, 17, Sri Malani Housing Co-operative Society, Indian Air Line Colony, Trinulgherry, Secunderabad – 500 015", as an eligible project or scheme for a further period of three years, without any change in the approved cost of Rs. 6.22 crore commencing with the financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 6/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

**का.आ. 1234 (अ).**— जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 04.10.2012 की अधिसूचना सं. सां. आ. 2366 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "दत्त सामाजिक सेवा ट्रस्ट, ए/पी सौखायदा कॉलोनी-विंग, करद जिला, सतारा, महाराष्ट्र" द्वारा "मौजूदा सुविधाओं का संचालन" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 9.25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 31 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ; तथापि, कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियम, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर धारा 35 क ग के तहत कोई छूट लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "दत्त सामाजिक सेवा ट्रस्ट, ए/पी सौखायदा कॉलोनी-विंग, करद जिला, सतारा, महाराष्ट्र" द्वारा चलाई जा रही "मौजूदा सुविधाओं का संचालन" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए 9.25 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) कंपनी अधिनियम और कंपनियों (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर धारा 35 कग के तहत कोई छूट लागू नहीं होगी।

[सं. 7/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ( एन. सी)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29<sup>th</sup> March, 2016

**S.O. 1234(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2366(E) dated 4.10.2012 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 31, “Running of existing facilities” by “Dutt Samajik Seva Trust, A/p Saukhyada Colony – wing, Karad district Satara, Maharashtra”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 9.25 crore for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Running of existing facilities” which is being carried out by “Dutt Samajik Seva Trust, A/p Saukhyada Colony – wing, Karad district Satara, Maharashtra”, as an eligible project or scheme for a further period of three years, without any change in the approved cost of Rs. 9.25 crore commencing with the financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 7/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

**का.आ. 1235(अ).**—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 07.5.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1030(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “वनवासी युवा संगठन, पो.ओ. खरोद तालुका. घोघाम्बा जिला पंचमहल, गुजरात” द्वारा “अनाथ छात्रों के विद्यालय का विस्तार और संचालन” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 1.19 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 2 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली,

1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ; तथापि, कंपनी अधिनियम और कंपनियों (सीएसआर) नियम, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर धारा 35 कग के तहत कोई छूट लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “वनवासी युवा संगठन, पो.ओ. खरोद तालुका. घोघाम्बा जिला पंचमहल, गुजरात” द्वारा चलाई जा रही “अनाथ छात्रों के विद्यालय का विस्तार और संचालन” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए 1.19 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) कंपनी अधिनियम और कंपनियों (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर धारा 35 कग के तहत कोई छूट लागू नहीं होगी।

[सं. 8/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ (एन.सी)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2016

**S.O. 1235(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1030(E) dated 7.5.2012 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 2, “Expansion & running of school ORPHAN student” by “The Vanvasi Yuva Sangthan, P.O. Kharod TA. Ghoghamba District Panchmahal, Gujarat”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 1.19 crore for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Expansion & running of school ORPHAN student”, which is being carried out by “The Vanvasi Yuva Sangthan, P.O.Kharod TA. Ghoghamba District Panchmahal, Gujarat”, as an eligible project or scheme for a further period of three years without any change in the approved cost of Rs. 1.19 crore commencing with the financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 8/2016/F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

**का.आ. 1236(अ).**—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 04.10.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 2366(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “ओम क्रिएशन ट्रस्ट, आनंद निकेतन, किंग जॉर्ज वी

मेमोरियल, डॉ० ई मोसेस रोड, महालक्ष्मी, मुंबई-400011" द्वारा "भूमि और भवन परियोजना" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 37.70 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 9 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ; तथापि, कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियम, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर धारा 35 कग के तहत कोई छूट लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "ओम क्रिएशन ट्रस्ट, आनंद निकेतन, किंग जॉर्ज वी मेमोरियल, डॉ० ई मोसेस रोड, महालक्ष्मी, मुंबई-400011" द्वारा चलाई जा रही "भूमि और भवन परियोजना" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए 37.70 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर धारा 35 कग के तहत कोई छूट लागू नहीं होगी।

[सं. 9/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ (एन.सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2016

**S.O. 1236(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2366(E) dated 4.10.2012 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 9, "Land and Building project" by "Om Creations Trust, Anand Niketan, King George V Memorial, Dr. E Moses Road, Mahalaxmi, Mumbai – 400 011", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 37.70 crore for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Land and Building project" which is being carried out by "Om Creations Trust, Anand Niketan, King George V Memorial, Dr. E Moses Road, Mahalaxmi, Mumbai – 400 011", as an eligible project or scheme for a further period of three years, without any change in the approved cost of Rs. 37.70 crore commencing with the financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18;

(b) The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 9/2016/F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

**का.आ. 1237(अ).—**जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 17.11.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2907(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “नोएडा लोक मंच, डी-134, सेक्टर-15, नोएडा - 201301” द्वारा “i) नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी, ii) संस्कार केंद्र स्कूल, होशियारपुर गांव, सेक्टर-51, नोएडा, iii) संस्कार केंद्र स्कूल, घड़ी चॉकंदी, सेक्टर-68, नोएडा, iv) संस्कार केंद्र स्कूल, सरका गांव, नोएडा” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 9 पर अधिसूचित किया था और जिसे दिनांक 9.10.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 2411(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा “नोएडा लोक मंच, डी-134, सेक्टर-15, नोएडा - 201301” द्वारा चलाई जा रही “i) नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी, ii) संस्कार केंद्र स्कूल, होशियारपुर गांव, सेक्टर-51, नोएडा, iii) संस्कार केंद्र स्कूल, घड़ी चॉकंदी, सेक्टर-68, नोएडा, iv) संस्कार केंद्र स्कूल, सरका गांव, नोएडा” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए 169 लाख रुपए और 155 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

(ख) धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 10/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ (एन.सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th March, 2016

**S.O. 1237(E).—**Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.2907 (E) dated 17<sup>th</sup> November, 2009, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 9, “i) Noida Public Library, ii) Sanskar Kendra School, Hoshiarpur Village, Sector 51, Noida, iii) Sanskar Kendra School, Ghari Chawkandi, Sector-68, Noida, iv) Sanskar Kendra School, Sarka Village, Noida” by Noida Lok Manch, D-134, Sector 15, Noida-201301, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was further extended vide S.O. No. 2411(E) dated 9.10.2012 for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-

tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- Section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project "i) Noida Public Library, ii) Sanskar Kendra School, Hoshiarpur Village, Sector 51, Noida, iii) Sanskar Kendra School, Ghari Chawkandi, Sector-68, Noida, iv) Sanskar Kendra School, Sarka Village, Noida" which is being carried out by Noida Lok Manch, D-134, Sector 15, Noida-201301, without any change in the approved cost of Rs. 169 lakh and Rs. 155 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18.

(b) The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 10/2016/F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

**का.आ. 1238(अ).—**जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 22.11.1994 की अधिसूचना सं. का.आ. 839(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "बीईई ईएनएन चैरिटेबल ट्रस्ट, तालाब तिल्लों रोड, जम्मू-180002" द्वारा "तालाब तिल्लों रोड, जम्मू में उपस्कर और फर्निचर के साथ 16,449 वर्ग फुट क्षेत्रफल में 80 बिस्तरों वाले सामान्य अस्पताल के भवन का निर्माण" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1995-96 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 8 पर विनिर्दिष्ट किया था; ; जिसे बाद में दिनांक 17.03.1997 की अधिसूचना सं. का.आ. 214(अ०) के द्वारा निर्धारण वर्ष 1998-99 को प्रारंभ होने वाले तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 17.11.2000 की अधिसूचना सं. का.आ. 1029(अ०) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2001-02 को प्रारंभ होने वाले तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 30.10.2003 की अधिसूचना सं. सां०आ० 1244(अ०) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2004-05 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 29.03.2007 की अधिसूचना सं. सां०आ० 486(अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 30.12.2010 की अधिसूचना सं. सां०आ० 3064(अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. सां०आ० 661(अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के इक्कीस वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियों (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "बीईई ईएनएन चैरिटेबल ट्रस्ट, तालाब तिल्लों रोड, जम्मू-180002" द्वारा चलाई जा रही "तालाब तिल्लों रोड, जम्मू में उपस्कर और फर्निचर के साथ 16,449 वर्ग फुट क्षेत्रफल में 80 बिस्तरों वाले सामान्य अस्पताल के भवन का निर्माण" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17

और 2017-18 के लिए 238.88 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[(सं. 11/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2016

**S.O. 1238(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.839(E) dated the 22<sup>nd</sup> November, 1994, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 8, for Construction of building of 80 beded General Hospital in an area of 16,449 Sq. ft. with equipment and furniture at Talab Tillo Road, Jammu by BEE ENN Charitable Trust, Talab Tillo Road, Jammu-180002, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1995-1996 which was extended further vide notification number S.O.214(E) dated the 17<sup>th</sup> March, 1997 for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999 which was extended further vide notification number S.O.1029(E) dated the 17<sup>th</sup> November, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002; which was extended further vide notification number S.O.1244(E) dated the 30<sup>th</sup> October, 2003 for a period of three year beginning with assessment year 2004-2005, which was extended further vide notification number S.O.486(E) dated 29<sup>th</sup> March, 2007 for a period of three year beginning with financial year 2008-09 and which was extended further vide notification number S.O.3064 (E) dated 30<sup>th</sup> December, 2010 for a period of three year beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. 661 (E) dated 12<sup>th</sup> March, 2013 for a period of three year beginning with financial year 2012-13;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twenty one years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- Section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project for Construction of building of 80 beded General Hospital in an area of 16,449 Sq. ft. with equipment and furniture at Talab Tillo Road, Jammu, which is being carried out by BEE ENN Charitable Trust, Talab Tillo Road, Jammu-180002, without any change in the approved cost of Rs. 238.88 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18.

(b) The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 11/2016/F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

**का.आ. 1239(अ).**—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 7.05. 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1030(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “सर्वोदय विकास समिति, जी.टी. रोड, सैदाबाद, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-221508”

द्वारा “टंकण, आशुलिपि प्रशिक्षण” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 16.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 9 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा “सर्वोदय विकास समिति, जी.टी. रोड, सैदाबाद, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-221508” द्वारा चलाई जा रही “टंकण, आशुलिपि प्रशिक्षण” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए 16.80 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

(ख) धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 12/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ (एन.सी)]

मक्खन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2016

**S.O. 1239(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1030(E) dated 7.5.2012 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 9, “Type, Shorthand training” by “Sarvodaya Vikas Samiti, G.T. Road, Saidabad, Allahabad, Uttar Pradesh – 221 508”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 16.80 crore for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Type, Shorthand training”, which is being carried out by “Sarvodaya Vikas Samiti, G.T. Road, Saidabad, Allahabad, Uttar Pradesh-221 508”, as an eligible project or scheme for a further period of three years without any change in the approved cost of Rs. 16.80 crore commencing with the financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 12/2016/F. No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

**का.आ. 1240(अ).—**जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 627(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “बसावनागुडी एक्वेटिक सेंटर, पंपामाहकावी रोड, शंकरपुरम, बसावनागुडी, बेंगलूरु-560004, कर्नाटक” द्वारा “इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 2.67 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 13 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा “बसावनागुडी एक्वेटिक सेंटर, पंपामाहकावी रोड, शंकरपुरम, बसावनागुडी, बेंगलूरु-560004, कर्नाटक” द्वारा चलाई जा रही “इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए 2.67 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

(ख) धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 13/2016 /फा. सं. वी-27015/1/2016 एस ओ (एन.सी)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th March, 2016

**S.O. 1240(E).—**Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 627(E) dated 12.3.2013 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 13, “International Standard Swimming Pool” by Basavanagudi Aquatic Centre, Pampamahakavi Road, Shankarpuram, Basavanagudi, Bangalore – 560 004, Karnataka”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 2.67 crore for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “International Standard Swimming Pool”, which is being carried out by “Basavanagudi Aquatic Centre, Pampamahakavi

Road, Shankarpuram, Basavanagudi, Bangalore – 560 004, Karnataka”, as an eligible project or scheme for a further period of three years without any change in the approved cost of Rs. 2.67 crore commencing with the financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18.

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 13/2016/F. No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

**का.आ. 1241(अ).—**जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 04.10.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 2366(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “अर्चना एजुकेशनल ट्रस्ट, 81, लास पलमास, आठवां तल, लिटिल जिब्स रोड, मुम्बई-400006 ” द्वारा “संतोष महेश बगरोएडा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 166.93 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 16 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “अर्चना एजुकेशनल ट्रस्ट, 81, लास पलमास, आठवां तल, लिटिल जिब्स रोड, मुम्बई-400006 ” द्वारा चलाई जा रही “संतोष महेश बगरोएडा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए 166.93 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[(सं. 14/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2016

**S.O. 1241(E).—**Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2366(E) dated 4.10.12 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 16, “Santosh Mahesh Bagroida Vocational Training Center ” by Archana Educational Trust, 81, Las Palmas, 8th Floor, Little Gibbs Road, Mumbai – 400006”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 166.93 lakh for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Santosh Mahesh Bagroia Vocational Training Center”, which is being carried out by “Archana Educational Trust, 81, Las Palmas, 8th Floor, Little Gibbs Road, Mumbai – 400006”, as an eligible project or scheme for a further period of three years without any change in the approved cost of Rs. 166.93 lakh commencing with the financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18.

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 14/2016/F. No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

**का.आ. 1242(अ).**—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 18.03.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 614(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “भारत सेवाश्रम संघ, 211, रास बिहारी एवेन्यू, कोलकाता- 700019, पश्चिम बंगाल” द्वारा “जनजातिय और पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु कार्यक्रम” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-2010 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 10 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 640(अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाले तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छः वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “भारत सेवाश्रम संघ, 211, रास बिहारी एवेन्यू, कोलकाता- 700019, पश्चिम बंगाल” द्वारा चलाई जा रही “जनजातिय और पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु कार्यक्रम” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए 5.82 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[(सं. 15/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ (एन.सी)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th March, 2016

**S.O. 1242(E).**—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 614(E) dated 18<sup>th</sup> March, 2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 10, “Tribal and backward class Welfare programme” by Bharat Sevashram Sangha, 211, Rash Behari Avenue, Kolkata –700019, West Bengal, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was further extended vide S.O. No. 640(E) dated 12.3.2013 for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-Section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Tribal and backward class Welfare programme” which is being carried out by Bharat Sevashram Sangha, 211, Rash Behari Avenue, Kolkata –700019, West Bengal, without any change in the approved cost of Rs. 5.82 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18.

[No. 15/2016/F. No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

**का.आ. 1243(अ).**—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.04.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 743(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “चिल चिल एशियन मिशन सोसायटी, कांगलाटोंगबी-795151, मणिपुर” द्वारा “गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के छात्रों का उद्धार” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 30.01 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 22 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “चिल चिल एशियन मिशन सोसायटी, कांगलाटोंगबी-795151, मणिपुर” द्वारा चलाई जा रही “गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के छात्रों का उद्धार” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए 30.01 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है; चूंकि वित्तीय वर्ष 2014-15 पहले ही समाप्त हो चुका है अतः आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 क ग के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा;

(ख) धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[(सं. 16/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ (एन.सी)]

मक्खन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2016

**S.O. 1243(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 743(E) dated 11.4.2011 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 22, “Upliftment of ST students through quality education” by Chil Chil Asian Mission Society, Kanglatongbi –795151, Manipur”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 30.01 crore for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Upliftment of ST students through quality education”, which is being carried out by “Chil Chil Asian Mission Society, Kanglatongbi –795151, Manipur”, as an eligible project or scheme for a further period of three years without any change in the approved cost of Rs. 30.01 crore commencing with the financial year 2014-15 i.e. 2014-15, 2015-16 and 2016-17. As the financial year 2014-15 has already been lapsed, no certificate under Section 35AC of the IT Act, 1961 would be issued for the financial year 2014-15;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 16/2016/F. No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)